बचत योजना पर मिलेगा तगड़ा ब्याज

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर मिलेगा वही तगड़ा रिटर्न, सरकार ने नहीं बदली दरें

निवेशकों के लिए खुशखबरी- एनएससी और एससीएसएस की ब्याज दरें

9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नही

नई दिल्ली, 31 मार्च.सरकार ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे निवेशकों को स्थिर और भरोसेमंद रिटर्न मिलता रहेगा.

पीपीएफ ,एसएसवाई और एनएससी जैसी योजनाओं की दरें लगातार 9वीं बार यथावत रखी गई हैं.इससे मिडिल क्लास निवेशकों और सुरक्षित निवेश चाहने वालों को राहत मिली है, जो लंबे समय से इन स्कीम्स को भरोसेमंद विकल्प मानते हैं.केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों को एक बार फिर बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा है.यह लगातार 9वीं तिमाही है जब पीपीएफ, एसएसवाई और एनएससी जैसी योजनाओं की दरों में स्थिरता बनी हुई है. इससे उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, जो सुरक्षित और निश्चित रिटर्न वाले विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं.सरकार द्वारा जारी दरों के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना और एससीएसएस पर 8.2 प्रतिशत का सबसे अधिक ब्याज मिल रहा है.

वहीं, एनएससी पर 7.7 प्रतिशत, 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी और किसान विकास पत्र पर 7.5त्न तथा मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है.पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4त्न की दर जारी है.इन ब्याज दरों को हर तिमाही में सरकार द्वारा समीक्षा के बाद तय किया जाता है.इसके लिए श्यामला गोपीनाथ समिति के फॉर्मूले का पालन किया जाता है, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले 0.25 प्रतिशत से 1प्रतिशत अधिक रिटर्न सुनिश्चित किया जाता है .साथ ही महंगाई और बाजार में नकदी की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है.

रुपया 95 प्रति डॉलर के पार उतरने के बाद संभला, 15 पैसे मजबूत

मुंबई, 31 मार्च. भारी उतार-चढ़ाव के बीच पहली बार 95 रुपये प्रति डॉलर से भी ज्यादा कमजोर होने के बाद रुपया अंत में 15 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में आज रुपये की शुरुआत 123.25 पैसे की जबरदस्त तेजी के साथ 93.62 रुपये प्रति डॉलर पर हुई. प्रारंभ में ही यह 93.57 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. लेकिन इसके बाद इसका ग्राफ लगातार नीचे उतरता गया और दोपहर बाद एक समय यह 95.2275 रुपये प्रति डॉलर तक टूट चुका था. पहली बार एक डॉलर 95 रुपये का बोला गया. हालांकि बाद में वापसी करते हुए भारतीय मुद्रा 15.25 पैसे की बढ़त में 94.70 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई.

आरबीआई ने नए नियम की तारीख बढ़ाकर जुलाई की

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी 3 महीने की राहत

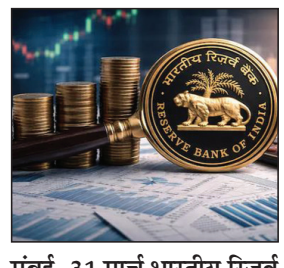

मुंबई, 31 मार्च.भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैपिटल मार्केट और कॉरपोरेट लोन से जुड़े नए नियमों की डेडलाइन को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2026 कर दिया है.यह फैसला बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फीडबैक के बाद लिया गया, जिन्होंने इन नियमों को लागू करने के लिए अधिक समय की मांग की थी.

नए नियम खासतौर पर कंपनियों के मर्जर, अधिग्रहण और बाजार में फंडिंग के तरीकों को प्रभावित करेंगे.इससे सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है.भारतीय बैंकिंग और कैपिटल मार्केट के लिए अहम फैसले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए लोन और फंडिंग नियमों को लागू करने की तारीख तीन महीने आगे बढ़ा दी है.पहले ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले थे, लेकिन अब बैंक और वित्तीय संस्थान इन्हें 1 जुलाई 2026 से लागू करेंगे.

यह निर्णय बाजार सहभागियों और बैंकों से मिले फीडबैक के बाद लिया गया है, जिसमें तकनीकी और प्रक्रियात्मक तैयारियों के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत जताई गई थी.नया फ्रेमवर्क मुख्य रूप से यह तय करता है कि बैंक शेयर बाजार, ब्रोकर्स और कंपनियों के अधिग्रहण या विलय के लिए किस तरह और किन शर्तों पर फंडिंग कर सकेंगे.

इन नियमों के तहत कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को राहत दी गई है, जिससे वे 100त्न कैश या समकक्ष सिक्योरिटी के आधार पर फंडिंग प्राप्त कर सकेंगे, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी .वहीं कंपनियों के अधिग्रहण के लिए बैंक लोन लेना आसान किया गया है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब अधिग्रहण के जरिए कंपनी पर नियंत्रण हासिल किया जा रहा हो .इसके अलावा, रीफाइनेंसिंग के नियमों को सख्त किया गया है .अब कंपनियां केवल तभी नया लोन लेकर पुराने कर्ज को चुका सकेंगी, जब डील पूरी तरह संपन्न हो चुकी हो .

ईरान युद्ध लंबा चला तो महंगे हो सकते हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर

नई दिल्ली, 31 मार्च. पश्चिम एशिया संकट के कारण मेमोरी और चिपसेट की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने लगी है और युद्ध लंबा चलने की स्थिति में मोबाइल फोन, कंप्यूटर और उस डिवास के दाम बढ़ सकते हैं, जिनमें इनका इस्तेमाल होता है.

भारत में नोकिया इंडिया की प्रबंधक विभा मेहरा ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी करने के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि युद्ध के कारण दूसरी चीजों के साथ मेमोरी और चिपसेट की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है. अभी डिवाइसों की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पर्याप्त इनवेंटरी उपलब्ध है, लेकिन युद्ध जारी रहा तो मध्यम अवधि में असर दिखने लगेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल मेमोरी और चिपसेट के दाम बढ़ने लगे हैं. कुछ लोगों ने इनका भंडारण शुरू कर दिया है और दाम बढ़ा दिये हैं. ऐसे में तुरंत नहीं तो आने वाले कुछ समय में इसका असर जरूर दिखेगा. इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2026 जारी करते हुए श्रीमती मेहरा ने कहा कि भारत में डाटा उपभोग तेजी से बढ़ रहा है.

पिछले पांच साल में 21.7 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ता हुआ कुल डाटा ट्रैफिक साल 2025 में 27.6 एग्जाबाइट मासिक पर पहुंच गया. वहीं प्रति यूजर औसत मासिक डाटा खपत 18.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ पिछले साल 31.1 जीबी पर रहा.

5 लाख में इलेक्ट्रिक कार का सपना

नई दिल्ली, 31 मार्च. भारतीय ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स किफायती ईवी सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है. खबरों के मुताबिक, कंपनी 2026-2027 तक बहुप्रतीक्षित टाटा नानो इवी लॉन्च कर सकती है, जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपये के आसपास हो सकती है.फिलहाल टाटा टिएगो कंपनी की सबसे सस्ती कार बनी हुई है.

इस कदम से आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना और आसान हो सकता है.भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा मोटर्स अब किफायती सेगमेंट में बड़ा कदम उठाने जा रही है.

एफपीआई ने की 1 .27 लाख करोड़ बिकवाली

भारतीय पूंजी बाजार से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध निकासी की है

मुंबई, 31 मार्च. पश्चिम एशिया संकट और रुपये में जारी तेज गिरावट के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजार में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. शुद्ध बिकवाली उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है.

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा कंपनी सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने मार्च में पूंजी बाजार से कुल 1,26,991 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की जो अपने-आप में रिकॉर्ड है. कोरोना काल में मार्च 2020 के बाद यह पहला मौका है जब एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध निकासी की है. मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब एफपीआई ने 1,18,203 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी. इक्विटी से एफपीआई ने मार्च में 1,17,775 करोड़ रुपये निकाले जिसका असर शेयर बाजारों पर साफ दिखा. महीने के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही. यह पहला मौका है जब एक ही महीने में इक्विटी में एफपीआई निवेश में एक लाख करोड़ रुपये

डेट में उनकी शुद्ध बिकवाली 8,469 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 2,616 करोड़ रुपये रही . हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने कुल 1,852 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया . इससे पहले, फरवरी में एफपीआई ने पूंजी बाजार में शुद्ध रूप से 37,847 करोड़ रुपये लगाये थे जबकि जनवरी में वे बिकवाल रहे थे . पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में एफपीआई शुद्ध रूप से बिकवाल रहे हैं . उन्होंने इस दौरान भारतीय पूंजी बाजार से 1,52,741 करोड़ रुपये निकाले हैं . तीन वित्त वर्षों में यह पहला मौका है जब एफपीआई का शुद्ध निवेश नकारात्मक रहा है .

महिला उद्यमी 6सिग्मा क्वालिटी प्रणाली का मंत्र अपनायें : वैष्णव

नई दिल्ली, 31 मार्च. रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्योग संभाल रही महिलाओं को अपने संगठन और आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6सिग्मा (99.9997 प्रतिशत शुद्धता) की संस्कृति अपनाने का आह्वान किया है.

श्री वैष्णव यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के महिला प्रभाग फिक्की लेडीज़ ऑर्गनाइजेशन के 42वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. सम्मेलन को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया. इस सम्मेलन में फिक्की-एफएलओ ने उद्यमशीलता विकास, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व विकास और आम जन की रोज़ी-रोटी से जुड़े क्षेत्रों में कार्य के जरिए शहरी और ग्रामीण भारत में अपनी बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया. दो दिन के सम्मेलन में उद्योग, मीडिया, राजनीति और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी जानी-मानी महिला हस्तियां शामिल हुईं.

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिला उद्यमी कंपनियों के सामाजिक दायित्व के कार्यों और कौशल विकास से ऊपर उठ कर नयी वास्तविकताओं का सामना करे और अपने संगठन में 6सिग्मा गुणवत्ता प्रणाली को अपना मंत्र बनायें. उन्होंने कहा कि उद्यमियों को कच्चा माल और सेवाएं देने वाले अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिल कर इस संस्कृति को बढ़ाना होगा क्यों कि यह केवल लागत ही नहीं गुणवत्ता और नवाचार अस्तित्व का प्रश्न बन गया है. उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा उन देशों से है जिन्होंने गुणवत्ता, नवाचार तथा लागत दक्षता की अपनी संस्कृति से लम्बे समय से अपनी पहचान बनायी है. उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ सबसे एडवांस्ड सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रहा है.

श्री वैष्णव ने कहा कि भारत आज चार लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था है और उससे बढ़ रहा है . आगे क्वालिटी, नवचार और कार्य की दक्षता विश्व में हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता को तय करेंगी . मैं फिक्की एफएलाओ जैसे संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे सुगठित प्रणाली और एआई अपनाने में पहल करें, खासकर एप्लिकेशन लेवल पर, ताकि इंडस्ट्रीज़ में सार्थक बदलाव लाया जा सके और राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया जा सके .

एक महीने में 11 फीसदी लुढ़का सेंसेक्स

छह साल में पहली बार सालाना गिरावट

मुंबई, 31 मार्च. पश्चिम एशिया संकट के कारण मार्च में प्रमुख सूचकांकों में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गयी है और कोरोना काल के बाद छह साल में पहली बार वित्त वर्ष के दौरान इसने नकारात्मक रिटर्न दिया है.

वित्त वर्ष 2025-26 के आखिरी कारोबारी दिवस पर सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 71,947.55 अंक पर बंद हुआ. पूरे वित्त वर्ष के दौरान इसमें 5,467.37 अंक यानी 7.06 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी. वित्त वर्ष 2019-20 के बाद यह पहला मौका है जब सेंसेक्स ने नकारात्मक रिटर्न दिया है.

कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से मार्च 2020 में शेयर बाजारों में भारी गिरावट रही थी और 2019-20 में सेंसेक्स 23.80 प्रतिशत टूटा था. खास बात यह रही कि पहले 11 महीने में फरवरी 2026 तक सेंसेक्स 3,872.27 अंक ऊपर था, लेकिन मार्च में यह 9,339.64 अंक यानी 11.49 प्रतिशत का गोता लगा गया. पश्चिम एशिया संकट के कारण एक तरफ निवेशक बाजार में जोखिम लेने से कतरा रहे हैं तो दूसरी तरफ रुपया कमजोर होता जा रहा है.

केंद्र का राजकोषीय घाटा फरवरी तक 80 प्रतिशत पर

नई दिल्ली, 31 मार्च. केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीने में फरवरी 2026 तक पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत को पार कर गया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 27,91,943 करोड़ रुपये रही, जो संशोधित अनुमान का 82 प्रतिशत है. इस दौरान कुल व्यय 40,44,592 करोड़ रुपये रहा जो संशोधित अनुमान का 81.5 प्रतिशत है.

इंडिगो का नया कप्तान : विलियम वाल्श संभालेंगे सीईओ पद

नई दिल्ली, 31 मार्च. इंडिगो का सीईओ नियुक्त किया है. वॉल्श 3 अगस्त 2026 से यह जिम्मेदारी संभालेंगे, हालांकि उनकी नियुक्ति अभी रेगुलेटरी मंजूरी के अधीन है. वर्तमान में वे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं.

कंपनी का मानना है कि उनके नेतृत्व में इंडिगो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी.भारतीय एविएशन सेक्टर में एक बड़े बदलाव के तहत इंडिगो ने अनुभवी उद्योग विशेषज्ञ विलियम वाल्श को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है. वॉल्श 3 अगस्त 2026 से पदभार संभालेंगे. फिलहाल वे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत हैं, जहां उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होगा.

समाचार विशेष

छोटे मुस्लिम दल, कांग्रेस की सक्रियता पड़ेगी भारी?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनावों से पहले अल्पसंख्यक वोट बैंक के बदलते समीकरण, छोटे मुस्लिम संगठन, उत्तर बंगाल में कांग्रेस की सक्रियता तथा जनता की कई शिकायतें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी सत्ता बचाये रखने में कठिन चुनौती बन सकते हैं.

करीब 15 साल तक अल्पसंख्यक मतदाता तृणमूल की चुनावी ताकत का मुख्य आधार रहे हैं. अब करीब 30 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने की होड़ लगी हुई है, जो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 114 से अधिक सीट के नतीजों को प्रभावित करते हैं.

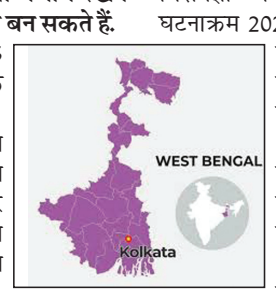

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के नेता नौशाद सिद्दीकी, तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी का एआईएमआईएम के साथ गठबंधन और मुर्शिदाबाद व मालदा में कांग्रेस की फिर से सक्रियता ने बंगाल के अल्पसंख्यक चुनावी समीकरण में नई अनिश्चितता पैदा की है. विशेषज्ञों ने कहा कि यह घटनाक्रम 2026 के विधानसभा चुनावों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, पहले अल्पसंख्यक मतदाता लगभग सहज रूप से तृणमूल के पीछे खड़े रहते थे, मुख्य रूप से भाजपा के कारण. हालांकि नए दलों और स्थानीय शिकायतों के उभरने से छोटे स्तर पर हलचल पैदा हुई है, जो कड़े मुकाबले वाले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है.

कांग्रेस पारंपरिक गढ़ में फिर से सक्रिय

कांग्रेस मालदा और मुर्शिदाबाद में अपने पारंपरिक गढ़ में फिर से सक्रिय होने का प्रयास कर रही है, जिन जिलों में तृणमूल के उभरने से पहले वह अल्पसंख्यक राजनीति में हावी थी . कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन यह दिखाता है कि अल्पसंख्यक मतदाता अपनी राजनीतिक पसंद पर फिर विचार कर रहे हैं . उन्होंने कहा, 2024 के लोकसभा चुनावों में वाम दलों के साथ चुनाव लड़ने पर मुर्शिदाबाद और मालदा में विपक्ष का मत प्रतिशत बढ़ा . हम 2023 में सागरदिगी उपचुनाव में तृणमूल को हरा भी चुके हैं .

फडणवीस-उद्धव मीटिंग, यू-टर्न की आहट!

महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पक रहा है नया?

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और विधायक आदित्य ठाकरे के बीच बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई है.

यह बैठक विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के दालन में हुई, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है. सूत्रों के मुताबिक यह बैठक पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे हुई और इसमें मुख्य रूप से विधायकों को फंड नहीं मिलने के मुद्दे पर चर्चा की गई है. महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सामने यह शिकायत रखी थी कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त निधि नहीं मिल रही है. इसी मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और उनके साथ मौजूद विधायकों को आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही निधि उपलब्ध कराई जाएगी. इस आश्वासन को बैठक का सबसे बड़ा निष्कर्ष माना जा रहा है, जिससे फिलहाल राजनीतिक तनाव कम होने की संभावना जताई जा रही है.

विदाई के दिन खास मुलाकात

इस पूरे घटनाक्रम को और खास बनाता है यह तथ्य कि वह दिन उद्धव ठाकरे का विधान परिषद सदस्य के रूप में आखिरी दिन था . इसी दिन विधान परिषद में विदाई भाषण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की कार्यशैली और योगदान की सराहना की. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद फडणवीस की ओर से की गई यह प्रशंसा सदन में सकारात्मक माहौल का संकेत मानी जा रही है . फडणवीस और ठाकरे जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच इस तरह की बैठक हमेशा खास मानी जाती है .

भाजपा को नहीं मिली पसंद की सीटें

चेन्नई. तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया. उसने ई पलानीस्वामी से कई नेताओं के विरोध के बावजूद उनको एनडीए में जोड़ा और एक मजबूत गठबंधन बना कर डीएमके, कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी की. लेकिन खबर है कि भाजपा को खुद भी अपनी पसंद की सीटें नहीं मिलीं.

पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना डीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने उसे ज्यादा मुश्किलें सीटें दीं. सिर्फ भाजपा को ही नहीं, बल्कि दूसरी सहयोगी पार्टियों को भी कठिन सीटें मिली हैं. अगर संख्या की बात करें तो जरूर भाजपा को पिछली बार की 20 सीट के मुकाबले 27 सीटें मिली हैं. लेकिन पसंद की सीटें नहीं हैं.बताया जा रहा है कि भाजपा कोयम्बटूर की तीन सीटें चाह रही थी, जिसमें एक सीट सिन्गनालूर सीट भी है, जहां से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई लड़ना चाहते थे. लेकिन अन्ना डीएमके ने वह सीट नहीं छोड़ी.

विशेष क्या प्रद्युत बोरदोलोई बचा पाएंगे भाजपा का किला, क्यों फंसेगा पेच?

असम : दिसपुर में होगा महासंग्राम!

गुवाहाटी. असम की राजनीति का केंद्र 'दिसपुर' न केवल राज्य की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि यह गुवाहाटी का एक ऐसा हाई-प्रोफाइल चुनावी क्षेत्र भी है जो पूरे राज्य की सियासी दिशा तय करता है. साल 1973 से असम की राजधानी के रूप में कार्य कर रहे दिसपुर में 9 अप्रैल 2026 को मतदान होना है.

इस बार यहां की लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि साख और वफादारी की भी है. जहां एक तरफ भाजपा ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक 'टर्नकोट' नेता को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

दिसपुर सीट पर इस बार सबसे बड़ा उलटफेर भाजपा के खेमे में देखने को मिला है. पार्टी ने दो बार के विजेता सिटिंग विधायक अतुल बोरा का टिकट काटकर हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को अपना उम्मीदवार बनाया है. बोरदोलोई ने कांग्रेस में 'घुटन' महसूस होने का हवाला देते हुए भाजपा का दामन थामा था. हालांकि, इस फैसले ने भाजपा के भीतर ही बगावत के सुर तेज कर दिए हैं. अतुल बोरा ने इसे 'विश्वासघात' करार दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने या प्रतिद्वंद्वियों को समर्थन देने के संकेत दिए हैं, जिससे भाजपा की 'सुनिश्चित जीत' की राह में कांटे बिछ सकते हैं.

परिसीमन में बदल गया सियासी भूगोल- 2023 के परिसीमन अभ्यास ने दिसपुर विधानसभा के मतदाता आधार को पूरी तरह बदल दिया है. कभी 4 लाख से अधिक मतदाताओं वाला यह क्षेत्र अब 2,43,176 मतदाताओं का एक कॉम्पैक्ट और शहरी निर्वाचन क्षेत्र बन गया है. ग्रामीण इलाकों और कई बूथों के हटने से अब यह निर्वाचन क्षेत्र 67.84 प्रतिशत शहरी आबादी वाला बन चुका है. सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव से मुस्लिम (11.40 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (7.82 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (7.03 प्रतिशत) के मतदाताओं का समीकरण भी प्रभावित हुआ है, जो अब नए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है.

त्रिकोणीय मुकाबला

भाजपा के प्रद्युत बोरदोलोई को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपनी तेजतर्रार नेता मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को मैदान में उतारा है, जो कभी बोरदोलोई की ही सहयोगी रही हैं . वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने भी शहरी इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बल्लभ पात्रा को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है . दिसपुर, जो असम सचिवालय और विधान सभा जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का घर है, वहां की जागरूक शहरी जनता इस बार दलबदल और स्थानीय मुद्दों के बीच अपना फैसला सुनाएगी .